

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं सामाजिक समानता: वंचित एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक अवसरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

चक्रपाणि

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग
गंजडुंडवारा पी. जी. कॉलेज, गंजडुंडवारा, कासगंज, उत्तर प्रदेश
अजय शंकर
असिस्टेंट प्रोफेसर (टीचर एजुकेशन)
गंजडुंडवारा पी. जी. कॉलेज गंजडुंडवारा कासगंज, उत्तर प्रदेश

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.23259960>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 21-07-2026

Accepted: 20-08-2026

Published: 25-09-2026

Keywords:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,
सामाजिक समानता, वंचित
वर्ग, शैक्षिक अवसर,
सामाजिक स्तरीकरण,
सामाजिक गतिशीलता।

ABSTRACT

शिक्षा किसी भी समाज में केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक अवसरों के वितरण, सामाजिक गतिशीलता और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय समाज में जाति, वर्ग, लिंग, जनजातीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर शैक्षिक अवसरों में असमानता लंबे समय से देखी जाती रही है। विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा व्यवस्था को अधिक समतामूलक, समावेशी और अवसरपरक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत पहल प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए किए गए प्रमुख शैक्षिक प्रावधानों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना तथा यह समझना है कि ये प्रावधान सामाजिक समानता और सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

तथा मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय समाज सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं से निर्मित एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति केवल उसकी व्यक्तिगत योग्यता से निर्धारित नहीं होती, बल्कि जाति, वर्ग, लिंग, आर्थिक स्थिति, जनजातीय पहचान, निवास क्षेत्र और अन्य सामाजिक परिस्थितियाँ भी उसके अवसरों को प्रभावित करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा का प्रश्न केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय तक पहुँच का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि यह सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय से सीधे जुड़ जाता है। जिस समाज में शिक्षा के अवसरों का वितरण असमान होता है, वहाँ पहले से मौजूद सामाजिक असमानताएँ आगे भी बनी रहने की संभावना रहती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा को सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक गतिशीलता दोनों से जोड़कर देखा जाता है। एक ओर शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करके सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अवसर देती है, वहीं दूसरी ओर यदि शिक्षा की पहुँच ही सामाजिक और आर्थिक रूप से असमान हो, तो शिक्षा स्वयं असमानता को पुनरुत्पादित करने का माध्यम बन सकती है। बोरदियू और पासेरों (Bourdieu & Passeron, 1977) ने शिक्षा और सामाजिक पुनरुत्पादन के संबंध को स्पष्ट करते हुए बताया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों में अंतर शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित कर सकता है। भारतीय संदर्भ में यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक रूप से जाति, वर्ग और सामाजिक स्थिति ने शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित किया है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के सार्वभौमीकरण और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अनेक संवैधानिक एवं नीतिगत प्रयास किए गए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए विभिन्न योजनाओं एवं सकारात्मक उपायों के माध्यम से शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में निरंतरता, डिजिटल संसाधनों तक पहुँच और रोजगारोन्मुख शिक्षा के अवसरों में असमानता अभी भी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न हैं।

इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का महत्व सामने आता है। नीति ने शिक्षा को अधिक समावेशी और समानतापूर्ण बनाने के लिए Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) की अवधारणा को विशेष महत्व दिया है। नीति के अनुसार सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की पहचान तथा उनकी शैक्षिक भागीदारी में सुधार शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, दिव्यांग व्यक्ति तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है (Ministry of Education, 2020)।

NEP 2020 की विशेषता यह है कि यह केवल विद्यालय में प्रवेश बढ़ाने की बात नहीं करती, बल्कि शिक्षा में access, participation, quality और inclusion को व्यापक रूप से देखने का प्रयास करती है। नीति में लैंगिक समानता के लिए Gender Inclusion Fund, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए लक्षित प्रयास तथा उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में कई प्रावधान किए गए हैं। इस दृष्टिकोण से शिक्षा को सामाजिक असमानताओं को कम करने और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के साधन के रूप में देखा जा सकता है।

इस संदर्भ में NEP 2020 का अध्ययन केवल शिक्षा संबंधी नीतिगत दस्तावेज के रूप में करना पर्याप्त नहीं होगा। इसे सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक बहिष्करण, समान अवसर और सामाजिक गतिशीलता की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के संदर्भ में समझना अधिक उपयोगी है। विशेष रूप से यह देखना आवश्यक है कि नीति के प्रावधान उन समूहों के लिए वास्तविक अवसरों का विस्तार किस सीमा तक कर सकते हैं, जो ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से शिक्षा की मुख्यधारा में अपेक्षाकृत पीछे रहे हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र इसी प्रश्न पर केंद्रित है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के वंचित एवं कमजोर वर्गों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार अध्ययन का केंद्रीय सरोकार यह समझना है कि NEP 2020 भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की असमानता को कम करके सामाजिक समानता और सामाजिक गतिशीलता के लिए किस प्रकार आधार तैयार कर सकती है।

2. शोध के उद्देश्य एवं शोध-पद्धति

3.1 शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में वंचित एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक अवसरों तथा सामाजिक समानता के बीच संबंध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

1. भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और शैक्षिक अवसरों के बीच संबंध को समझना।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए किए गए प्रमुख शैक्षिक प्रावधानों का अध्ययन करना।
3. यह विश्लेषण करना कि NEP 2020 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा तक पहुँच और भागीदारी को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है।
4. शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक समानता की संभावनाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
5. नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के सामने मौजूद प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत चुनौतियों की पहचान करना।

3.2 शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। शोध के लिए प्राथमिक आँकड़ों का संकलन नहीं किया गया है, बल्कि विषय से संबंधित उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्टें एवं दस्तावेज, UDISE+, All India Survey on Higher Education (AISHE), UNESCO की रिपोर्टें तथा सामाजिक समानता और शिक्षा से संबंधित प्रकाशित अकादमिक साहित्य शामिल हैं।

अध्ययन में उपलब्ध सामग्री का केवल विवरण प्रस्तुत करने के बजाय उसे समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के आधार पर विश्लेषित किया गया है। विशेष रूप से सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक बहिष्करण, समान अवसर, सामाजिक गतिशीलता और समावेशन को विश्लेषण के प्रमुख आधार के रूप में लिया गया है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा की असमान पहुँच किस प्रकार व्यापक सामाजिक असमानताओं से जुड़ी है और NEP 2020 इन असमानताओं को कम करने के लिए किस प्रकार की संभावनाएँ प्रस्तुत करती है।

अध्ययन में नीति के प्रावधानों के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन से संबंधित संभावित सामाजिक एवं संस्थागत चुनौतियों को भी ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार शोध-पद्धति का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि NEP 2020 में वंचित वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, बल्कि यह भी समझना है कि वे प्रावधान भारतीय समाज में समान शैक्षिक अवसर और सामाजिक गतिशीलता स्थापित करने में किस सीमा तक सहायक हो सकते हैं।

इस अध्ययन की प्रमुख सीमा यह है कि यह द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अतः इसके निष्कर्ष प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण या किसी विशिष्ट राज्य अथवा जिले की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि उपलब्ध नीतिगत एवं अकादमिक सामग्री के समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर आधारित हैं।

3. भारतीय समाज में सामाजिक असमानता एवं शैक्षिक अवसर

भारतीय समाज सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं से निर्मित है। जाति, वर्ग, लिंग, आर्थिक स्थिति, जनजातीय पहचान तथा ग्रामीण-शहरी पृष्ठभूमि जैसे कारक व्यक्ति के सामाजिक अवसरों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा भी इन सामाजिक संरचनाओं से अलग नहीं है। जिन समूहों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचना अपेक्षाकृत आसान होता है, जबकि वंचित समूहों को अनेक स्तरों पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार शैक्षिक असमानता भारतीय समाज में विद्यमान व्यापक सामाजिक असमानता का ही एक महत्वपूर्ण रूप है।

जाति भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक कारक रही है। स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक प्रावधानों, आरक्षण तथा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित वंचित समूहों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाइयाँ तथा गुणवत्तापूर्ण संस्थानों तक असमान पहुँच जैसी समस्याएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। इसलिए केवल विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है; शिक्षा को पूरा करने और उसके बाद आगे बढ़ने के अवसर भी समान होने चाहिए।

आर्थिक स्थिति भी शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शिक्षा से संबंधित परिवहन, अध्ययन सामग्री, डिजिटल उपकरण और अन्य खर्च कठिनाई पैदा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर यह समस्या और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बजाय जल्दी रोजगार की ओर जाने के लिए बाध्य हो सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता शिक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानता को आगे भी बनाए रख सकती है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक सुविधाओं का अंतर भी महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, जबकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों तथा तकनीकी संसाधनों की कमी चुनौती बन सकती है। जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक दूरी भी शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती है।

इसी प्रकार डिजिटल तकनीक के विस्तार ने शिक्षा के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता एक नई चुनौती के रूप में सामने आई है। जिन विद्यार्थियों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, वे डिजिटल शिक्षा के अवसरों का समान रूप से लाभ नहीं उठा पाते। इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में और स्पष्ट हो सकता है।

इन परिस्थितियों से स्पष्ट है कि शैक्षिक असमानता किसी एक कारण का परिणाम नहीं है। जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति, लिंग और क्षेत्र कई बार एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है जो केवल सभी को समान अवसर देने की बात न करे, बल्कि वंचित समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानकर उन्हें आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराए। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समावेशी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है।

यही कारण है कि NEP 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को विशेष महत्व दिया गया है। यदि नीति के समावेशी प्रावधान प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो शिक्षा सामाजिक असमानता को कम करने और वंचित समूहों के लिए सामाजिक गतिशीलता के अवसर बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। लेकिन इसके लिए शिक्षा तक पहुँच के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता, निरंतरता, समानता और सामाजिक रूप से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी और समानतापूर्ण बनाना है। नीति यह स्वीकार करती है कि सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। इसी संदर्भ में नीति में Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, दिव्यांगजन तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित अन्य समूहों को शामिल किया गया है (Government of India, 2020)।

नीति का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें केवल विद्यालय में प्रवेश बढ़ाने के बजाय शिक्षा में पहुँच, भागीदारी, गुणवत्ता और निरंतरता को समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहायता और संस्थागत सुविधाओं के विस्तार जैसे उपाय उनकी शिक्षा को जारी रखने में सहायक हो सकते हैं।

NEP 2020 में लैंगिक समानता को भी विशेष महत्व दिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं को कम करने के लिए Gender Inclusion Fund का प्रावधान किया गया है। इसका

उद्देश्य उन क्षेत्रों और समूहों की बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना है जहाँ लैंगिक असमानता अधिक दिखाई देती है। इससे माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लड़कियों की निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। विशेष रूप से जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों की उपलब्धता, परिवहन, शिक्षक तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी एवं सुलभ शैक्षिक वातावरण विकसित करना भी सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नीति में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। डिजिटल तकनीक शिक्षा की पहुँच को बढ़ाने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसके लिए डिजिटल उपकरण, इंटरनेट और डिजिटल दक्षता की समान उपलब्धता आवश्यक है।

इस प्रकार NEP 2020 में वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों का उद्देश्य केवल शिक्षा में संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पहुँच, भागीदारी, निरंतरता और समान अवसर को मजबूत करना है। SEDGs पर विशेष ध्यान, Gender Inclusion Fund, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन, ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान तथा उच्च शिक्षा के विस्तार जैसे प्रावधान सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, इन प्रावधानों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कितनी प्रभावी और समान रूप से लागू किया जाता है।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सामाजिक समानता की संभावनाएँ: समाजशास्त्रीय विश्लेषण

समाजशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण माध्यम है। विशेष रूप से वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, रोजगार के अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आधार बन सकती है। NEP 2020 में ऐसे समूहों की शिक्षा पर विशेष ध्यान इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वंचित वर्गों के विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा और रोजगार तक पहुँच बनाते हैं, तो उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार शिक्षा पीढ़ीगत असमानता को कम करने में भी योगदान दे सकती है। Bourdieu और Passeron (1977) ने शिक्षा और सामाजिक संरचना के संबंध को स्पष्ट करते हुए बताया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों का शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वंचित समूहों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता देना सामाजिक समानता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

NEP 2020 का समावेशी दृष्टिकोण सामाजिक बहिष्करण को कम करने की संभावना भी प्रस्तुत करता है। यदि विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न सामाजिक समूहों की समान भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो शिक्षा सामाजिक संपर्क और सामाजिक एकीकरण का माध्यम बन सकती है। इसके लिए संस्थानों में भेदभाव-मुक्त और सम्मानजनक वातावरण आवश्यक है।

शिक्षा का संबंध आर्थिक सशक्तिकरण से भी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए यह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि रोजगार और आय में सुधार से परिवार की सामाजिक स्थिति मजबूत हो सकती है तथा अगली पीढ़ी के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

महिलाओं की शिक्षा भी सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण आधार है। बालिकाओं की शिक्षा बढ़ने से उनके रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय-निर्माण और सामाजिक भागीदारी के अवसर बढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से NEP 2020 में Gender Inclusion Fund जैसे प्रावधान लैंगिक समानता की दिशा में उपयोगी पहल हैं।

फिर भी सामाजिक समानता केवल शिक्षा नीति से स्वतः स्थापित नहीं हो सकती। आर्थिक असमानता, डिजिटल विभाजन, जातिगत पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़ियाँ और ग्रामीण-शहरी अंतर जैसी सामाजिक परिस्थितियाँ शिक्षा के परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसलिए NEP 2020 की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन और अन्य सामाजिक-आर्थिक नीतियों के साथ समन्वय पर निर्भर करेगी।

अतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से NEP 2020 शिक्षा को सामाजिक समानता और गतिशीलता का महत्वपूर्ण साधन बनाने की संभावना रखती है। इसकी वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब वंचित समूहों को केवल शिक्षा में प्रवेश ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निरंतरता, उच्च शिक्षा और शिक्षा के बाद समान अवसर भी प्राप्त हों।

इस प्रकार समाजशास्त्रीय दृष्टि से NEP 2020 सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। इसकी सबसे बड़ी संभावना यह है कि शिक्षा को सामाजिक पृष्ठभूमि से स्वतंत्र होकर अवसर प्राप्त करने का माध्यम बनाया जाए। लेकिन यह संभावना तभी वास्तविकता बनेगी जब नीतिगत प्रावधान, पर्याप्त संसाधन, प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन एक साथ आगे बढ़ें।

7. प्रमुख चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक विमर्श

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक समानता, समावेशन और वंचित एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके बावजूद इन प्रावधानों को वास्तविक सामाजिक परिवर्तन में

बदलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारतीय समाज में शैक्षिक असमानता केवल आर्थिक संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, सामाजिक पृष्ठभूमि और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता जैसे अनेक कारक इसे प्रभावित करते हैं। इसलिए NEP 2020 की सफलता केवल उसके नीतिगत प्रावधानों से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी और समान क्रियान्वयन से निर्धारित होगी।

नीति और क्रियान्वयन के बीच अंतर इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। NEP 2020 में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में शिक्षा की आधारभूत स्थिति समान नहीं है। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों, परिवहन, पुस्तकालय तथा तकनीकी संसाधनों की कमी नीति के उद्देश्यों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नीतिगत लक्ष्यों को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रभावी प्रशासन और नियमित निगरानी आवश्यक है।

आर्थिक असमानता भी शैक्षिक समानता के सामने एक बड़ी बाधा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री, परिवहन, डिजिटल उपकरण और उच्च शिक्षा से जुड़े खर्च शिक्षा जारी रखने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं के कारण विद्यार्थी शिक्षा के बजाय रोजगार को प्राथमिकता देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में केवल विद्यालय में प्रवेश उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा। छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता और अन्य सहयोगी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

डिजिटल विभाजन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की एक नई चुनौती है। NEP 2020 शिक्षा में तकनीक और डिजिटल संसाधनों के उपयोग को महत्वपूर्ण मानती है, लेकिन सभी विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और आवश्यक डिजिटल दक्षता समान रूप से उपलब्ध नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी इससे विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए डिजिटल शिक्षा का विस्तार तभी सामाजिक समानता में योगदान देगा जब डिजिटल संसाधनों की पहुँच भी व्यापक और न्यायपूर्ण हो।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ भी शिक्षा में समान अवसरों को प्रभावित करती हैं। जातिगत पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़ियाँ, सामाजिक भेदभाव तथा परिवार की पारंपरिक मान्यताएँ कई विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा बन सकती हैं। विशेष रूप से कुछ परिस्थितियों में बालिकाओं को घरेलू जिम्मेदारियों, सुरक्षा संबंधी चिंताओं या परिवार की सीमित आर्थिक क्षमता के कारण शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में कठिनाई होती है। इसलिए समानता के लिए शैक्षिक संस्थानों के साथ-साथ परिवार और समुदाय के स्तर पर भी सामाजिक जागरूकता आवश्यक है।

ग्रामीण-शहरी असमानता भी महत्वपूर्ण चुनौती है। शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों, कोचिंग तथा डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, जबकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी विद्यार्थियों के अवसरों को प्रभावित करती है। इस अंतर को कम करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक सुविधाओं का विकास तथा दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इसके साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक समानता का अर्थ केवल यह नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर ले। वास्तविक समानता तब होगी जब विभिन्न सामाजिक समूहों के विद्यार्थियों को समान स्तर की शिक्षण-अधिगम सुविधाएँ और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। इसलिए NEP 2020 के प्रभाव का मूल्यांकन केवल नामांकन के आधार पर नहीं, बल्कि शिक्षा में निरंतरता, सीखने के परिणाम, उच्च शिक्षा में भागीदारी और रोजगार के अवसरों के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा अकेले सामाजिक असमानता को समाप्त नहीं कर सकती। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन व्यक्ति के अवसरों पर परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक नेटवर्क और रोजगार की संरचना का भी प्रभाव रहता है। Bourdieu और Passeron (1977) ने शिक्षा और सामाजिक संरचना के संबंध को स्पष्ट करते हुए बताया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों का शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वंचित समूहों को केवल समान अवसर देना ही नहीं, बल्कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त सहायता देना भी आवश्यक है।

अतः NEP 2020 को सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन माना जा सकता है, लेकिन इसे सामाजिक असमानता का पूर्ण समाधान नहीं समझा जा सकता। इसकी वास्तविक सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि वंचित एवं कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को केवल शिक्षा में प्रवेश ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निरंतरता, उच्च शिक्षा और शिक्षा के बाद समान सामाजिक एवं आर्थिक अवसर कितनी प्रभावी रूप से प्राप्त होते हैं। यही प्रक्रिया शिक्षा को सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी माध्यम में परिवर्तित कर सकती है।

8. निष्कर्ष एवं सुझाव

8.1 निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में शैक्षिक असमानता व्यापक सामाजिक असमानताओं से जुड़ी हुई है। जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति, लिंग, जनजातीय स्थिति तथा ग्रामीण-शहरी अंतर जैसे कारक विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों को अलग-अलग स्तर पर प्रभावित करते हैं। इसलिए सामाजिक समानता

स्थापित करने के लिए केवल शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता पर्याप्त नहीं है; उन सामाजिक समूहों के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं जो ऐतिहासिक, आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा में पीछे रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल प्रस्तुत करती है। Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) पर विशेष ध्यान, लैंगिक समावेशन, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुँच और उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार जैसे प्रावधान सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं (Ministry of Education, 2020)।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से NEP 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता के साधन के रूप में देखा जा सकता है। यदि वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा तक समान अवसर प्राप्त होते हैं, तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। इसका प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा और रोजगार के माध्यम से अगली पीढ़ी के अवसरों को भी प्रभावित कर सकता है।

हालाँकि, नीति के प्रावधान अपने आप सामाजिक समानता सुनिश्चित नहीं कर सकते। आर्थिक कठिनाइयाँ, डिजिटल विभाजन, सामाजिक भेदभाव, ग्रामीण-शहरी असमानता और गुणवत्तापूर्ण संस्थानों तक असमान पहुँच जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इसलिए नीति और उसके क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करना आवश्यक है।

8.2 सुझाव

- पहला, वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक कारणों से विद्यार्थी शिक्षा बीच में न छोड़ें।
- दूसरा, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। विशेष रूप से परिवहन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान आवश्यक है।
- तीसरा, डिजिटल शिक्षा के विस्तार के साथ डिजिटल असमानता को कम करना जरूरी है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उपकरण, इंटरनेट और डिजिटल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- चौथा, सामाजिक समानता के लिए केवल नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता, सीखने के परिणाम और उच्च शिक्षा में प्रवेश की नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
- पाँचवाँ, शिक्षण संस्थानों में जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए संवेदनशील और समावेशी वातावरण विकसित किया जाना चाहिए।



- छाठा, उच्च शिक्षा में वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन, परामर्श, छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। केवल प्रवेश उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है; विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने और आगे रोजगार प्राप्त करने में भी सहयोग मिलना चाहिए।

अंततः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि नीतिगत प्रावधान समाज के सबसे वंचित व्यक्ति तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुँचते हैं। यदि शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता और परिणामों में सामाजिक अंतर को लगातार कम किया जाता है, तो शिक्षा भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। इसके लिए नीति, संस्थागत क्षमता और सामाजिक दृष्टिकोण—तीनों स्तरों पर एक साथ प्रयास करना आवश्यक है।

संदर्भ सूची (References)

1. Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in education, society and culture*. Sage Publications.
2. Government of India. (2009). *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009*. Ministry of Law and Justice.
3. Government of India. (2016). *The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016*. Ministry of Law and Justice.
4. Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education.
5. Government of India. (2021). *Women and men in India 2021: A statistical compilation*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
6. Government of India. (2022). *Educational statistics at a glance*. Ministry of Education.
7. Government of India. (2023). *UDISE+ 2022–23: Report on school education in India*. Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.
8. Government of India. (2024). *UDISE+ 2023–24: Report on school education in India*. Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.
9. Ministry of Education. (2021). *All India survey on higher education 2019–20*. Department of Higher Education, Government of India.
10. Ministry of Education. (2022). *All India survey on higher education 2020–21*. Department of Higher Education, Government of India.
11. Ministry of Education. (2023). *All India survey on higher education 2021–22*. Department of Higher Education, Government of India.



12. Ministry of Education. (2024). All India survey on higher education 2022–23. Department of Higher Education, Government of India.
13. National Council of Educational Research and Training. (2006). Position paper: National focus group on gender issues in education. NCERT.
14. National Council of Educational Research and Training. (2017). Educational statistics at a glance. NCERT.
15. National Sample Survey Office. (2019). Household social consumption on education in India: NSS 75th round (July 2017–June 2018). Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.
16. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
17. Singh, Y. (2004). Modernization of Indian tradition: A systematic study of social change. Rawat Publications.
18. Tilak, J. B. G. (2007). Inclusive growth and education: On the social foundations of human development. *Indian Journal of Human Development*, 1(1), 5–24.
19. UNESCO. (2017). Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). UNESCO.
20. UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education—All means all. UNESCO.
21. UNESCO. (2021). Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education. UNESCO.
22. UNICEF. (2021). Gender equality: Global annual results report 2021. UNICEF.
23. World Bank. (2018). World development report 2018: Learning to realize education’s promise. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1>
24. World Bank. (2022). World development report 2022: Finance for an equitable recovery. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1736-3>
25. World Bank. (2023). India: Education and skills development—Selected issues and opportunities. World Bank.